अध्याय १४

वेवल योजना
(Wavel Plan)

अक्तूबर १९४३ में वायसराय लिनलिथगो वापिस लन्दन बुला लिये गये। भारत छोड़ने से पूर्व उन्होंने दुर्गादास से कहा—आने वाले पचास वर्षों में भारत को स्वतन्त्र होने की आशा नहीं करनी चाहिए। अभी इस देश को संसदीय प्रणाली को सीखने में वर्षों का अभ्यास चाहिये और फिर अब तो एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था, जिससे अंग्रेजों का भारत में स्थायी तौर पर आवास सरल हो गया था।.....

लिनलिथगो को शायद दिवा स्वप्न देखने की आदत थी। उसने आँखें बन्द करके सोचा होगा कि अब समय की सुइयों ने चलना बन्द कर दिया होगा।

उसका उत्तराधिकारी, वेवल, इतना स्वप्नलोकीय नहीं था।

अक्तूबर १९४३ में ही फील्ड मार्शल लार्ड वेवल भारत में नये वायसराय बन कर आये। वो एक कुशल सैनिक अधिकारी थे और ज्यादा घुमाव-फिराव नहीं जानते थे। ऐसा माना जाता है, लिनलिथगो के स्थान पर वेवल को वायसराय बनाकर भेजने का कार्य अमरीकी दबाव के कारण किया गया था। अमरीका चाहता था कि भारत की समस्या का कोई उचित समाधान निकाला जाये और उसकी मान्यता थी कि पुराना वायसराय उसके मार्ग में बाधक था।

जिस समय वेवल को भारत में वायसराय बनाकर भेजा गया, उस समय इंग्लैंड में चर्चिल के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार कार्य कर रही थी। मई १९४५ में जब चर्चिल ने घोषणा की कि शीघ्र ही देश में चुनाव होंगे, तो श्रमिक नेता बेविन ने घोषणा की—"यदि हम सत्ता में आए तो हम इंडिया आफिस को बन्द कर देंगे और भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य बना कर देंगे।"[1]

---

1. BEVIN—"If we are returned we shall close the India Office and transfer this business to the Dominions."

Scanned with CamScanner

इंग्लैंड में श्रमिक दल के भारत सम्बन्धी नारे जनता में लोकप्रिय हो रहे थे और आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर चर्चिल के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह शीघ्र ही भारतीय समस्या का कोई समाधान करे और भारत में कोई उचित व्यवस्था करे।

भारत में नये वायसराय ने भी अनुभव किया कि जब तक इस देश के लोगों के मन में उत्तेजना, अशान्ति और अंग्रेजों के प्रति अविश्वास है तब तक यहां सुगमता-पूर्वक शासन नहीं किया जा सकता। उसने भी यही निष्कर्ष निकाला कि भारतीय समस्या का कोई हल होना ही चाहिये। वह जून में परामर्श के लिये लन्दन गया और लौटकर उसने एक घोषणा की। इस घोषणा में व्यक्त किये गये प्रस्तावों को—'वेवल योजना' कहते हैं। यह १४ जून १९४५ की बात है।

इस घोषणा के साथ ही भारत मन्त्री एमरी ने भी ऐलान किया कि कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्यों को मुक्त कर दिया जाएगा और दूसरे दिन नेताओं के लिये जेल के फाटक खोल दिये गये।

वेवल योजना की मुख्य बातें

वेवल योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं—

प्रथम— गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का फिर से गठन होगा। इसमें गवर्नर जनरल और सेनाओं के कमाण्डर-इन-चीफ को छोड़कर शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे।

दूसरा— सेना के अतिरिक्त शासन के सभी महत्वपूर्ण विभाग, केन्द्रीय स्तर पर, अब भारतीयों को सौंप दिये जाएँगे। यहाँ तक कि विदेश विभाग भी।

तीसरा—नई कार्यकारिणी परिषद में सवर्ण हिन्दुओं और मुसलमानों को समान रूप से प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। साथ ही हरिजनों, सिखों और ईसाईयों का भी प्रतिनिधित्व रहेगा।

चौथा— १९३५ के अधिनियम के अन्तर्गत भारत गवर्नर जनरल को जो विशेषाधिकार दिये गये हैं, उनका अकारण प्रयोग नहीं किया जाएगा।

पांचवाँ—यह एक तात्कालिक व्यवस्था है। युद्ध समाप्त होने पर भारत का नया संविधान स्वयं भारतीय ही बनायेंगे।

साथ ही यह भी कहा गया है कि इन प्रस्तावों के आधार पर शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन होगा। जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष तथा सभी प्रांतों के मुख्यमन्त्री तथा अन्य महत्वपूर्ण नेता भी बुलाये जायेंगे।

घोषणा के सम्बन्ध में कहा गया कि यह "ब्रिटेन की ओर से भारत की जनता को एक सर्वसम्मत राष्ट्रीय उपहार है।"[1]

---

1. WAVELL—"The offer is an agreed national offer on the part of this country to the people of India."

Scanned with CamScanner

इस उपहार में कोई विशेष नई बात नहीं थी। लगभग ऐसी ही योजना क्रिप्स भी प्रस्तुत कर चुके थे। बल्कि इसमें एक बहुत बुरी बात यह थी कि राष्ट्रीय कौंसिल में मुसलमानों को उतने ही स्थान दिए गए थे, जितने कि हिन्दुओं को। जबकि भारत की सत्तर प्रतिशत जनता हिन्दू थी। फिर भी सभी दलों ने इस योजना का स्वागत किया। कांग्रेस के लिए योजना का स्वागत करने का मुख्य कारण यह था कि इसके माध्यम से एक जड़ गतिरोध टूटने वाला था। यह एक अच्छी ही बात थी कि राष्ट्रीय कौंसिल में दो को छोड़कर शेष सभी सदस्य भारतीय ही होने वाले थे और फिर यह तो एक अन्तरिम व्यवस्था थी। भारत का नया संविधान तो भारतीयों को बनाना ही था।

शिमला सम्मेलन

२५ जून, १९४५।

शिमला की खुशनुमा फिजाओं में सम्मेलन प्रारम्भ हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सभी महत्वपूर्ण नेता इकट्ठे हुए। गांधी, नेहरू, आजाद, जिन्ना, लियाकत अली। अकाली नेता मास्टर तारासिंह भी थे और पंजाब के मुख्यमंत्री सिकन्दर हयात खान भी। अन्य प्रान्तों से भी मुख्यमंत्री आए। कुल, इक्कीस सदस्य।

सम्मेलन बड़े आशापूर्ण वातावरण में प्रारम्भ हुआ और ऐसा प्रतीत होता था कि निश्चित रूप से कोई समझौता हो जाएगा। सम्मेलन प्रारम्भ होने के समय वेवल ने आजाद से कहा था—"सम्मेलन में सम्मिलित किसी भी दल को दुराग्रह के कारण समझौते में व्यवधान बनने नहीं दिया जायेगा।"[1]

यह सोचकर कि निकट भविष्य में भारत आजाद होने वाला है, कांग्रेस ने यह नाजायज प्रस्ताव तक मान लिया था कि राष्ट्रीय कौंसिल में सवर्ण हिन्दुओं और मुसलमानों की संख्या समान होगी।

यह तय हुआ कि राष्ट्रीय कौंसिल में १४ सदस्य होंगे। चार हिन्दू, चार मुसलमान, एक सिक्ख, दो हरिजन और पंजाब की यूनियन पार्टी के मुख्य मन्त्री सिकन्दर हयात खान। शीघ्र ही कौंसिल के संगठन की तैयारी होने लगी। कांग्रेस ने जो पाँच हिन्दू सदस्य मनोनीत करने थे, उसके स्थान पर उसने दो हिन्दू; एक मुसलमान, एक पारसी और एक इसाई को कौंसिल की सदस्यता के लिये चुना।

इस तरह कौंसिल में पाँच के स्थान पर सात मुसलमान हुए, परन्तु जिन्ना साहब को इस पर भी एतराज था। उनका कहना था कि मुसलमानों को मनोनीत करने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग को है। यह एक अत्यन्त भोंडी मांग थी। इसका कांग्रेस और पंजाब के मुस्लिम मुख्यमन्त्री ने विरोध किया।

---

1. No party to the conference would be allowed to obstruct a settlement out of wilfullness."

Scanned with CamScanner

बस, फिर से गतिरोध उत्पन्न हो गया। एक अच्छा खासा समझौता हो गया था, जो जिन्ना की हठधर्मी के कारण टूट रहा था। बजाय इसके कि वायसराय उस गतिरोध को तोड़ते और अपनी निर्धारित योजना को क्रियान्वित करते उन्होंने ११ जुलाई को घोषणा कर दी कि वार्ता असफल हो गई है। सम्मेलन समाप्त कर दिया गया।

प्रश्न उठता है कि जब जिन्ना की सभी मांगें मान ली गई थीं, तो उसने सम्मेलन को असफल क्यों किया। उत्तर स्पष्ट है। जब शिमला में वार्ताएँ चल ही रही थी, उच्च अंग्रेज अधिकारियों ने जिन्ना से कहा कि यदि वे शिमला वार्ता को विफल कर देंगे तो उन्हें पाकिस्तान दे दिया जाएगा। ब्रिटिश अधिकारियों ने यह आश्वासन लन्दन के संकेत पर दिया था। **दुर्गादास** ने अपनी पुस्तक India from Curzon to Nehru and after में लिखा है—

> **"अपने होटल में जिन्ना, वायसराय के प्रस्तावों पर अपना निर्णय सुनाने वाले थे। परन्तु उससे थोड़ी ही देर पहले उन्हें शिमला में ब्रिटिश अधिकारियों के एक 'सैल' से, लन्दन का अनुदारवादियों के इशारों पर, एक सन्देश मिला–यदि जिन्ना वार्ता भंग कर देंगे, उन्हें पाकिस्तान से पुरस्कृत किया जायेगा।"[1]**

इसीलिए शिमला सम्मेलन की असफलता के बाद जब एक पत्रकार ने जिन्ना से पूछा जब आपकी यह मांग मान ली गई थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक समान दर्जा दिया जायेगा, तो फिर आपने वेवल प्रस्ताव क्यों ठुकराए। **जिन्ना** ने उत्तर दिया–**"जब मुझे प्लेट पर रखकर पाकिस्तान दिया जा रहा है, तो क्या मैं मूर्ख हूँ कि वेवल प्रस्ताव स्वीकार करूं।[2]"**

फ्रैंक मोरायस ने ठीक ही कहा है—"यदि वायसराय ने जिन्ना की हठधर्मी के बावजूद अपनी योजना को क्रियान्वित किया होता तो आज भारत का इतिहास ही और होता।"[3]

---

1. DURGA DAS—"He was expected to announce his final decision on the Viceroy's proposals to the Press at his hotel lounge. A few moments earlier, he had however, received a message from the 'cell' of British civil servants in Simla, which was in tune with the diehards in London that if Jinnah stepped out of the talks he would be rewarded with Pakistan.

2. JINNAH—"Am I a fool to accept this when I am offered Pakistan on a platter ?"

3. FRANK MORAES—"Had the Uiceroy proceeded to from the new Executive Council on the basis he had outlined, irrespective of the League, the political history of India might have been different."

Scanned with CamScanner